

विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन के स्रोतों का विकास करने और इसके वितरण (एफ एस डी और डी) तथा उपस्कर निर्माण (ईएम) के क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना

**1. उद्देश्य और कार्य-क्षेत्र :**

इस योजना के अधीन विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर विनिर्माण प्रतिष्ठानों को स्थापित करने / उनका विस्तार करने और विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला / तेल / गैस जैसे ईंधन की आपूर्ति के स्रोतों का विस्तार करने और इनका वितरण (रेल तंत्र/गैस पाइपलाइन आदि को जरिए) करने के लिए वि तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

**2. पात्र एंटिटी :**

सरकारी क्षेत्र :

- (क) प्रकटन की उपलब्धता
- (ख) पीएफसी द्वारा चूककर्ता घोषित न किया गया हो
- (ग) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों का विद्यमान चूककर्ता न हो
- (घ) \* संबंधित वित्त वर्ष का न्यूनतम आर ओ ई 12 प्रतिशत हो (अर्थात आसन्न पूर्ववर्ती वित्त वर्ष से पूर्व का वित्त वर्ष, जैसे कि 2009-10 के लिए संबंधित वित्त वर्ष 2011-12 होगा।)

\* एसपीवी रूट के माध्यम से विकसित की जा रही परि योजनाओं के मामले में लागू नहीं।

**प्राइवेट क्षेत्र :**

- (i) पीएफसी से वित्तीय सहायता चाहने वाली प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटी को पीएफसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता संबंधी मापदंडों को पूरा करना होगा, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंड शामिल होंगे-

- (क) निबल मूल्य पर प्राप्ति
- (ख) निबल मूल्य
- (ग) डी / ई अनुपात

- (घ) डी एस सी आर
- (ङ) रोकड़ प्रवाह
- (च) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के साथ ट्रेक रिकॉर्ड और क्रेडिट स्टैंडिंग
- (छ) प्रमोटर - कार्यनिष्पादन और पृष्ठभूमि
- (ज) ईक्विटी लाने की क्षमता
- (झ) ऋण जुटाने की योग्यता
- (ञ) बिक्री की व्यवस्था
- (ट) कारोबार की स्थिति
- (ठ) विदेशी प्रमोटरों की प्रतिबद्धता

(ii) प्रमोटर वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के वर्तमान चूककर्ता नहीं होने चाहिए।

### 3. उधार देने की दर और वित्तीय प्रभार :

उधारकर्ता एंटीटी / प्रमोटर की रेटिंग के अनुसार पीएफसी द्वारा समय-समय पर उधार देने की दर अधिसूचित की जाएगी।

वित्तीय प्रभार, विद्युत परियोजनाओं / योजनाओं के आरटीएल के संबंध में समय-समय पर लागू उधारकर्ताओं द्वारा देय होंगे (जिसमें अपफ्रंट शुल्क और प्रतिबद्धता प्रभार भी शामिल होंगे)।

### 4. वित्तपोषण की सीमा (परियोजना लागत का प्रतिशत)

|                  | एफ एस डी और डी | ई एम         |
|------------------|----------------|--------------|
| सरकारी क्षेत्र   | 80 प्रतिशत     | 80 प्रतिशत   |
| प्राइवेट क्षेत्र | 20 प्रतिशत     | * 50 प्रतिशत |

\* ऐसी परियोजनाओं के मामले में 70 प्रतिशत तक उच्च ऋण पर विचार किया जा सकता है, जिनमें परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए तक हो।

### 5. अधिकतम वापसी अवधि:

एफ एस डी और डी : 10 वर्ष

ई एम : मुख्य संयंत्र / उपस्कर विनिर्माता = 10 वर्ष

अन्य उपस्कर विनिर्माता = 7 वर्ष

## 5. प्रतिभूतियां :

- (i) राज्य / केंद्र सरकार की गारंटी / बैंक गारंटी / परिसंपत्तियों पर प्रभार
- (ii) निलंब (एस्करो) लेखा / साख पत्र

पीएफसी मूल्य निरूपण / श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर बल दे सकता है :-

- (i) निगम गारंटी
- (ii) प्रमोटर्स की वैयक्तिक गारंटी
- (iii) प्रमोटर्स के शेयरों को गिरवी रखना
- (iv) समूह / अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों पर प्रभार
- (v) निगम के पक्ष में सभी परियोजनाओं की संविदाओं, दस्तावेजों, बीमा पालिसियों का समनुदेशन
- (vi) न्यास और प्रतिधारण तंत्र स्थापित करना, ताकि परियोजनाओं की बिक्री से प्राप्त सभी आय का उपयोग पीएफसी द्वारा तय किए गए तरीके से किया जा सके।
- (vii) राजस्व पर प्रभार
- (viii) निगम को स्वीकार्य कोई अन्य प्रतिभूति